



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

असाधारण

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 13 फरवरी, 1981/24 माघ, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 13 फरवरी, 1981

क्रमांक एल० एल० आर० डी०(6)3/81.—हिमाचल प्रदेश विरोजा तथा विरोजा उत्पाद (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1981(1981 का अध्यादेश संख्यांक 1) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 213

के खण्ड(1) के अन्तर्गत दिनांक 13 फरवरी, 1981 को प्रख्यापित किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348(3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया जाता है ।

जय चन्द मलहोत्रा,
सचिव विधि ।

(अध्यादेश संख्या 1, 1981)

(हिमाचल प्रदेश विरोजा तथा विरोजा उत्पाद (व्यापार विनियमन)

अध्यादेश, 1981

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित

राज्य सरकार द्वारा ग्रन्थों का अपवर्जन करके विरोजा के क्रय तथा वितरण का व्यापार चलाये जाने और विरोजा पर आधारित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और तैयारी तथा उससे सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए जन साधारण के हित में व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश;

यतः हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित अध्यादेश जारी करते हैं :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. (1) यह अध्यादेश हिमाचल प्रदेश विरोजा तथा विरोजा उत्पाद (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1981 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ।

अध्याय II

बिरोजा व्यापार का विनियमन

2. इस अध्यादेश, में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं

(क) “प्राधिकृत अधिकारी” से राज्य सरकार का अधिकारी या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे वह अपनी ओर से बिरोजा क्रय या विक्रय के लिए और धारा 5 के अधीन अनुज्ञा पत्र देने के लिए प्राधिकृत हो,

(ख) “विहित” से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ग) “बिरोजा” से चीड़ या कैल के पेड़ों के छेवन द्वारा निकाला गया स्राव अभिप्रेत है,

(घ) “बिरोजा डिपो” से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसे मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा डिपो के रूप में उस डिपो के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निकाले गए बिरोजे के क्रय, संग्रह और विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ङ) “बिरोजा उत्पाद” से बिरोजे के प्रसंस्करण से प्राप्त व्युत्पादन अभिप्रेत है और इसमें बिरोजा, तारपीन, जमाया हुआ बिरोजा और सीधे बिरोजे से निर्मित पेंट तथा वार्निश भी समाविष्ट है,

(च) “बिरोजा छेवक” से बिरोजा छेवने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है,

(छ) “स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कब्जे, प्रबन्ध या नियन्त्रण में चीड़/चील या कैल के पेड़ हों,

(ज) “ईकाइ” से धारा 3 के अधीन गठित इकाई अभिप्रेत है,

(झ) जो शब्द तथा पद इस अध्यादेश में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

19

ईकाइयों का गठन।

3. राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य को उतनी इकाइयों में बांट सकती है जितनी वह उचित समझे, और जब तक ऐसी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन न किया जाए प्रत्येक वन खंड (जैसा वह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से तत्समय परिसीमित हो) एक ईकाइ होगी।

बिरोजा आदि के विक्रय, क्रय इत्यादि पर प्रतिबन्ध।

4. इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तिथि को या उसके पश्चात् :—

(क) कोई भी व्यक्ति जब तक की वह धारा 10 के अधीन और अनुसार पंजीकृत न हो, न बिरोजा छेवन करेगा, या न किसी बिरोजा उत्पाद का निर्माण करेगा और न किसी बिरोजा या बिरोजा उत्पाद का निर्यात करेगा,

(ख) कोई व्यक्ति राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को बिरोजा का विक्रय नहीं करेगा,

(ग) राज्य सरकार या इसके किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी बिरोजा छेवक/बिरोजा के स्वामी से बिरोजा क्रय नहीं करेगा,

(घ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति बिरोजा का परिवहन, निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर, नहीं करेगा—

(i) जहां वह बिरोजा का छेवक होने के कारण उसका परिवहन जिस क्षेत्र में बिरोजे का छेवन किया जाए उसके लिए विनिर्दिष्ट बिरोजा डिपो को करे, या

(ii) जहां वह इस राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से परिवहन करे,

(ङ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी ईकाई में निर्मित बिरोजा उत्पाद का उस ईकाई के बाहर किसी स्थान को ऐसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, इस सम्बन्ध में जारी किए गए अनुज्ञापत्र के बिना परिवहन नहीं करेगा।

विक्रय, परिवहन आदि के लिए अनुज्ञापत्र

5. (1) धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाएं:—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से पूर्व कोई बिरोजा क्रय किया हो, ऐसा बिरोजा परिवहन करने तथा राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है तथा राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को उसका क्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है, या

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसने राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से बिरोजा उत्पाद के निर्माण करने के लिए बिरोजा क्रय किया हो, उसके परिवहन और किसी बिरोजा जिसे वह बिरोजा उत्पादों के निर्माण में उपयोग करने में असमर्थ रहा हो, को विक्रय करने की अनुज्ञा दे सकता है, या

(ग) किसी व्यक्ति को जिसने हिमाचल प्रदेश के बाहर बिरोजा क्रय किया हो उसे राज्य के अन्दर लाने की अनुज्ञा या तो राज्य में बिरोजा उत्पादों के निर्माण के लिए या हिमाचल प्रदेश से बाहर अन्यत्र उनके परिवहन के लिए दे सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है विहित शुल्क के देने का दायी होगा।

6. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के लिए और प्रत्येक ईकाई के लिए जिसमें बिरोजा का छेवन किया जाता हो, एक सलाहकार समिति गठित करेगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट नौ से अनधिक सदस्य होंगे।

सलाहकार
समिति का
गठन।

(2) प्रत्येक ऐसी ईकाई की सलाहकार समिति राज्य सरकार को समय-समय पर उचित और युक्तियुक्त कीमत निर्धारित करने के लिए, जिस पर उस ईकाई में विक्रय के लिए प्रस्तुत बिरोजा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय किया जा सके, सलाह देगी और ऐसे अन्य विषयों पर भी सलाह देगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) समिति का कार्य विहित रीति से संचालित किया जाएगा।

7. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कीमत निर्धारित करेगी जिस पर वर्ष पर्यन्त प्रत्येक ईकाई में उसके द्वारा या लिए बिरोजा क्रय किया जाएगा अर्थात्:--

राज्य सरकार
द्वारा कीमत
निर्धारित
करना।

(क) ईकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्ष के दौरान इस अध्यादेश के अधीन बिरोजा के लिए निर्धारित की गई कीमत, यदि कोई हो,

(ख) ईकाई में छेवे गए बिरोजे की किस्म,

(ग) परिवहन व्यय,

(घ) ईकाई में श्रमिक के लिए प्रचलित मजदूरी का सामान्य दर,

(ङ) बिरोजा निस्सारण का व्यय,

(च) बिरोजा पैक करने का व्यय जिसके अन्तर्गत उस डिब्बे का मूल्य भी है जिसमें बिरोजा दिया जाता है,

(छ) कोई अन्य तथ्य जिसे राज्य सरकार सुसंगत समझे।

(2) इस प्रकार निर्धारित कीमत राज्य सरकार द्वारा निदेशित रीति से प्रकाशित की जाएगी, और जिस वर्ष के सम्बन्ध में वह हो, उसके दौरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) इस प्रकार निर्धारित कीमत बिरोजा के शुद्ध भार के लिए होगी, जिसमें उस डिब्बे का भार सम्मिलित न होगा जिसमें बिरोजा पैक हो।

(4) यदि धारा 6 के अधीन सलाहकार समिति गठित कर दी गई हो तो राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन कीमत निर्धारित करने के पूर्व, जहां व्यवहार्य हो, उससे परामर्श करेगी।

राज्य सरकार
विक्रय के लिए
प्रस्तुत समस्त
बिरोजा क्रय
करेगी।

8. (1) राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी बिरोजा डिपो पर कार्य के सामान्य समय में उसे या उस के लिए विक्रयार्थ प्रस्तुत किये गये समस्त बिरोजा को धारा 7 के अधीन निर्धारित कीमत पर क्रय करने के लिए बाध्य होगी :

परन्तु यह कि प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे बिरोजे को क्रय न करने से इन्कार करने का अधिकार होगा, जो उसकी राय में बिरोजा उत्पाद का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त हो।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के बिरोजा क्रय करने से इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार इन्कार किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, और विहित रीति से, प्रभागीय वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी को (जिसे आग सक्षम अधिकारी कहा गया है) परिवाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर, सक्षम अधिकारी संक्षिप्त जांच करेगा और परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस दशा में, जब उसे क्रय करने से इन्कार करना अनुचित प्रतीत हो तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी को बिरोजा की मनाही उचित प्रतीत हो किन्तु उसकी राय में बिरोजा कम कीमत पर क्रय किया जा सकता है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे उस कीमत पर, जिसे वह उचित समझे, क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय के लिए प्रस्तुत किये गए बिरोजे का छेवन किसी ऐसी भूमि पर स्थित वृक्षों से किया गया हो जो राज्य सरकार, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्रीय कमेटी, या ग्राम पंचायत में निहित थी तो ऐसे बिरोजे का विनियोग कीमत का भुगतान किसे बिना, और केवल ऐसे संग्रह-प्रभार का, यदि कोई हो, भुगतान करके जिसे राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अवधारित करे, किया जा सकता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

वृक्षों का छेवन
जिनका छेवन
न किया जा
रहा हो।

9. (1) यदि राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी इकाई में छेवन योग्य आकार के किन्हीं चीड़/चील अथवा कैल के वृक्षों का छेवन नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा ऐसे वृक्षों के स्वामी से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे वृक्ष से छेवन आरम्भ करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् वृक्ष का स्वामी ऐसे नोटिस का अनुपालन न करे तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी बिरोजा निस्सारण के लिए विहित रीति से वृक्ष को छेवन करायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी वृक्ष से निस्सारित समस्त बिरोजा इस अध्यादेश और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बेच दिया जाएगा और उस का मूल्य उस में स छेवन व्यय काटने के पश्चात् ऐसे वृक्षों के स्वामी को दे दिया जायेगा।

10. बिरोजा का प्रत्येक छेवक, बिरोजा उत्पाद का प्रत्येक निर्माता और बिरोजा या बिरोजा उत्पाद का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, देने पर पंजीकरण का हकदार होगा।

बिरोजा छेवको
आदि का
पंजीकरण

11. राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये बिरोजा का विक्रय या अन्य प्रकार से निस्सारण ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित हो।

बिरोजा
निस्सारण

12. राज्य सरकार धारा 19 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़ कर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अध्यादेश या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य सहायक अरण्यपाल अथवा राज्य वन निगम के उप-मण्डल प्रबन्धक से अन्यून पद के किसी अधिकारी को प्रत्ययोजित कर सकती है जो ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उनका प्रयोग या सम्पादन करेगी।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

13. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, या कोई वन अधिकारी, इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है:—

प्रवेश करने,
तलाशी लेने;
अधिग्रहण
करने आदि
की शक्ति।

(i) बिरोजा या बिरोजा उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी व्यक्ति, जलयान गाड़ी या पात्र को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है,

(ii) किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है,

(iii) बिरोजा उत्पाद को जिसके सम्बन्ध में उसे यह सन्देह हो कि इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित जिसमें ऐसा बिरोजा रखा या पहुंचाना हो, अधिगृहीत कर सकता है।

1974 का 2

(2) तलाशी लेने और अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध जिस प्रकार लागू होते हैं उसी प्रकार से वे, यथाशक्य, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे।

शास्ति

1927 का 16

14. यदि कोई व्यक्ति इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में यह समझाएगा कि उसने वन अपराध किया है और बिरोजा अथवा बिरोजा उत्पाद को, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया जाता है, ऐसा अपराध किया जाने के सम्बन्ध में वन उपज समझा जाएगा और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध जैसे कि इस राज्य में प्रवृत्त हैं तदनुसार आवश्यक उपान्तरण सहित लागू होंगे।

15. (1) यदि इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा:

कम्पनियों
द्वारा अप-
राध।

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण हेतु सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अधिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया था उपेक्षाजनक है तो वह प्रबन्ध अधिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए.—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी समाविष्ट होगा, और

(ख) “निदेशक” का किसी फर्म के सम्बन्ध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का
संज्ञान।

16. किसी वन अधिकारी द्वारा जो रेंज अधिकारी के पद से कम का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दी गयी लिखित रिपोर्ट के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अध्यादेश
के उपबन्धों
का अधि-
भावी
प्रभाव।

17. किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखित में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

सद्भावपूर्वक
किये गये कार्यों
के सम्बन्ध में
अपवाद।

18. (1) इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से जो इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए अभिप्रेत हो, किसी हानि के लिए जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो या किसी क्षति के लिए जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने
की शक्ति।

19 (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) बिरोजा की मूल्य सूची का प्रकाशन,

(ख) इस अध्यादेश के अधीन जान्व करने की रीति,

(ग) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिन पर

धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है और ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिए देय फीस,

(घ) धारा 8 के अधीन जिस विरोजा को क्रय करने से इन्कार किया गया हो, उसका निस्सारण,

(ङ) धारा 9 के अधीन वृक्षों से विरोजा छेवने की रीति,

(च) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा और उसके लिए देय फीस,

(छ) किस्म का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विरोजा की विशिष्टियां,

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाए।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समय, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम दस दिनों की कालावधि के लिए जो उसके एक सत्र या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखा जाएगा और यदि, उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या क्रमवर्ती सत्रों के अन्तर्धान के पूर्व, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या फैसला करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर बनाये गये कोई नियम ऐसे भूतलक्षी दिनांक से बनाये जा सकते हैं जो ऐसे प्रारम्भ से पूर्व न थे।

20. जहां अध्यादेश के लागू होने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा दिये जाने की प्रत्याशा में किसी व्यापारी से विरोजा के विक्रय के लिए कोई संविदा कर ली थी और उस संविदा के अधीन व्यापारी को दिए जाने के लिए प्रत्याशित विरोजा की कीमत का कोई अग्रिम ऐसे व्यापारी से प्राप्त कर लिया हो तो इस बात के होत हुए भी, कि धारा 4 और 17 के उपबन्धों के कारण वह संविदा अध्यादेश के प्रवृत्त होने पर शून्य हो जाएगी, उक्त व्यक्ति और व्यापारी ऐसे अग्रिम का ब्योरा देते हुए एक संयुक्त आवेदन-पत्र वन मण्डल अधिकारी/अथवा उस द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को दे सकेंगे तथा तदोपरान्त उक्त अधिकारी इस मत का यथाविधि समाधान हो जाने पर कि उक्त व्यक्ति ने आवेदन-पत्र स्वेच्छा से दिया है, अधिकारी को यह निदेश दे सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की ओर से उस व्यापारी को पहले ही भुगतान की गई धनराशि को कम कर के) किसी ब्याज या प्रतिकर के बिना धारा 8 के अधीन विक्रय किये गये विरोजा के लिए उक्त व्यक्ति को देय कीमत में दिया जाए और ऐसे भुगतान की सीमा तक राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी का उस व्यक्ति के प्रति और उक्त व्यक्ति का व्यापारी के प्रति दायित्व उन्मुक्त हो जाएगा और उक्त व्यक्ति का कोई दायित्व उस अग्रिम के सम्बन्ध में कोई ब्याज या प्रतिकर देने के लिए नहीं होगा।

संक्रमण-
कालीन
उपबन्ध।

अमीनुद्दीन अहमद खान,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला :
दिनांक 13, फरवरी, 1981.

जे० सी० मल्होत्रा,
सचिव (विधि)।

(Authorised English text of the Himachal Pradesh Beroja Tatha Beroja Utpad (Beopar Vinnyman) Adhiyadesh, 1981 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

(Ordinance No. 1 of 1981)

THE HIMACHAL PRADESH RESIN AND RESIN PRODUCTS (REGULATION OF TRADE) ORDINANCE, 1981

Promulgated by the Governor in the Thirty-second Year of the Republic of India.

AN Ordinance to provide in the interest of the general public, for the carrying on by the State of the trade of purchase and distribution of resin to the exclusion of others, and for the regulation of manufacture and preparation of various articles based on resin and for matters connected therewith;

Whereas, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commence-
ment.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Resin and Resin Products (Regulation of Trade) Ordinance, 1981.

(2) It extends to the whole of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

CHAPTER II

REGULATION OF THE TRADE OF RESIN

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

- (a) "authorised officer" means an officer of the State Government or any other person who may be authorised by it to purchase or sell resin on its behalf and to grant permits under section 5;
- (b) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Ordinance;
- (c) "resin" means the secretion extracted by tapping from Chir or Kail trees;
- (d) "resin depot" means a place specified as such by the Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh for the purchase, storage and sale of resin tapped in an area specified in relation to that depot;
- (e) "resin products" means derivatives obtained by processing of resin, and includes resin, turpentine, hardened resin, and also includes paints and varnishes manufactured directly from resin;

16 of 1927

- (f) "tapper of resin" means a person who taps resin;
- (g) "owner" means, a person in possession, management or control of Chir/Chil or Kail trees;
- (h) "unit" means a unit constituted under section 3;
- (i) words and expressions used but not defined in this Ordinance and defined in the Indian Forest Act, 1927 as amended from time to time in its application to Himachal Pradesh, shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. The State Government may by notification in the Official Gazette divide the State into such numbers of units, as it may deem fit, and until varied by such notification, each Forest Division (as for the time being delimited by general or special orders of the State Government) shall constitute a unit.

Constitution of Units.

4. On and after the commencement of this Ordinance—

Restrictions on sale, purchase of resin etc.

- (a) no person shall tap resin or manufacture any resin product or export any resin or resin products, unless he is registered under and in accordance with section 10;
- (b) no person shall sell resin to any person other than the State Government or an authorised officer;
- (c) no person other than the State Government or authorised officer shall purchase resin from any tapper/owner of resin;
- (d) no person other than the State Government or an authorised officer shall transport resin except in the following cases:—
 - (i) where he being a tapper of resin transports it to the resin depot specified for the area where the resin is tapped; or
 - (ii) where he transports it on behalf of the State Government or an authorised officer.
- (e) no person other than the State Government or an authorised officer shall transport resin products manufactured in a unit to any place outside that unit without a permit issued in that behalf by such authority, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed—

5. (1) Notwithstanding anything in section 4, the State Government or an authorised officer may on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed—

Permit for sale, transport etc.

- (a) permit any person, who had purchased any resin before the commencement of this Ordinance to transport and sell such resin to any person other than the State Government or an authorised officer and permit any person other than the State Government or an authorised officer to purchase and transport the same; or
- (b) permit any person, who has purchased resin from the State Government or an authorised officer for manufacture of resin products to transport the same and to sell any resin which he has been unable to utilise in the manufacture of resin products; or
- (c) permit any person, who has purchased any resin outside Himachal Pradesh to bring the same inside the State either for manufacture of resin products within the State or for transporting them elsewhere outside Himachal Pradesh.

(2) A person to whom a permit is granted under sub-section (1) shall be liable to payment of such fee as may be prescribed.

Constitution
of an Advisory
Committee.

6. (1) The State Government shall for each year constitute for each unit in which resin is tapped, an Advisory Committee which shall consist of not more than 9 members nominated by the State Government.

(2) The Advisory Committee for each such unit shall advise the State Government in the matter of fixation from time to time of a fair and reasonable price at which resin offered for sale may be purchased by or on behalf of the State Government in that unit, and also on such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed.

Fixation of
price by
State Government.

7. The State Government shall, having regard to following factors, fix the price at which resin shall be purchased by or for it in each unit during the year, namely:—

- (a) the price of resin, if any, fixed under this Ordinance during the preceding three years in respect of the unit;
- (b) the quality of the resin tapped in the unit;
- (c) the cost of transport;
- (d) the general rate of wages for labour prevalent in the unit;
- (e) the cost of extraction of resin;
- (f) the cost of packing of resin including the cost of container in which resin is delivered;
- (g) any other factor which the State Government considers relevant.

(2) The price so fixed shall be published in such manner as the State Government may direct, and shall not be altered during the year to which it relates.

(3) The price so fixed shall be for net weight of resin excluding the weight of container in which resin is packed.

(4) Where an Advisory Committee has been constituted under section 6, it shall, wherever practicable, be consulted by the State Government before the fixation of price under sub-section (1).

State Government to
purchase all
resin offered
for sale.

8. (1) The State Government or the authorised officer shall be bound to purchase at the price fixed under section 7 all resin offered for sale to or for it during the normal hours of business at a resin depot:

Provided that it shall be open to an authorised officer to refuse purchase of such resin as in his opinion is not fit for the purpose of manufacture of resin products.

(2) Any person aggrieved by the authorised officer's refusal to purchase resin under the proviso to sub-section (1), may, within fifteen days from such refusal, and in the manner prescribed, complain to the Divisional Forest Officer or such other officer as may be empowered by the State Government in that behalf (hereinafter referred to as the competent officer).

(3) On receipt of a complaint under sub-section (2), the competent officer shall hold a summary inquiry and pass such order within thirty days of the receipt of the complaint as he may deem fit, and in case he finds such refusal to be improper, he may direct the authorised officer to purchase the same.

(4) Where the competent officer finds the refusal of the resin proper but in his opinion, the resin may be purchased at a lower price, he may direct the authorised officer to purchase the same at such lower price as he deems fit.

(5) Notwithstanding anything in sub-section (1), where the State Government or an authorised officer has reason to believe that any resin offered for sale was tapped from trees standing on any land which was vested in or belonged to the State Government, Cantonment Board, Municipal Corporation, Municipal Committee, Notified Area Committee or Gram Panchayat, such resin may be appropriated without payment of price, and on payment only of such collection charges, if any, as the State Government or an authorised officer may determine.

(6) The provisions of sub-sections (2) to (4) shall *mutatis mutandis* apply in relation to any action taken under sub-section (5).

(7) Every order passed under this section shall be final.

9. (1) If the State Government or an authorised officer finds that any Chir/Chil or Kail trees of tappable size standing in a unit is not being tapped, the State Government or an authorised officer may by notice require the owner of such trees to commence tapping of the same or to cause its tapping commenced within such time as may be prescribed.

Tapping of trees which are not being tapped.

(2) If after the service of the notice under sub-section (1), the owner of the trees fails to comply with such notice, the State Government or an authorised officer may, in the manner prescribed, cause the trees to be tapped for extraction of resin.

(3) All resin extracted from a tree under sub-section (2), shall be sold in accordance with the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder and the price thereof shall, after deducting the expenses of tapping, be paid to the owner of such trees.

10. Every tapper of resin, every manufacturer of resin product and every exporter of resin or resin products shall be entitled to registration on payment of such fee, to such authority and in such manner as may be prescribed.

Registration of tappers of resin etc

11. Resin purchased by the State Government or authorised officer shall be sold or otherwise disposed of in such manner as the State Government may by general or special order direct.

Disposal of resin.

12. The State Government may, except the power to make the rules under section 19, by general or special order, delegate any of its powers or functions under this Ordinance or the rules made thereunder to any officer not below the rank of Assistant Conservator of Forests, or the Sub-Divisional Manager of the State Forest Corporation, who shall exercise or perform the same, subject to such conditions or restrictions, if any, as the State Government may specify in the order.

Delegation of powers.

13. (1) Any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any Forest Officer may, with a view of securing compliance with the provisions

Power of entry, search, seizure, etc.

of this Ordinance or the rules made thereunder or to satisfying himself that the said provisions have been complied with—

- (i) stop and search any person, vessel, vehicle or receptacle used or intended to be used for the transport of resin or resin product;
- (ii) enter and search any place;
- (iii) seize resin or resin product in respect of which he suspects that any provision of this Ordinance or the rules made thereunder has been, is being or is about to be contravened along with the receptacle containing or carrying such resin.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

Penalty.

14. If any person contravenes any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, he shall be deemed to have committed a forest offence, and the resin or resin product, if any, in respect of which such offence is committed shall in relation to the commission of such offence be deemed to be forest produce, and the provisions of Chapter IX of the Indian Forest Act, 1927 as in force in this State shall accordingly apply with necessary modifications.

Offences by companies.

15. (1) If the person committing an offence under this Ordinance is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary and treasurer, director, manager or other officers of the company, such managing agent, secretary and treasurer, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall also be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

- (a) “company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Cognizance of offences.

16. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Ordinance except on a report in writing of the facts constituting such offence made by any Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or by such other officer as may be empowered by general or special order of the State Government in that behalf.

17. The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in any contract or other instrument.

Provisions of this Ordinance to have overriding effect. Saving in respect of acts done in good faith.

18. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or an authorised officer for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder or by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance or the rules made thereunder.

19. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out purposes of this Ordinance.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the publication of the price list of the resin;
- (b) the manner of holding inquiries under this Ordinance;
- (c) the authority by whom, the manner in which and the conditions subject to which permits may be issued under section 5 and the fee payable for such permits;
- (d) the disposal of the resin, the purchase of which was refused under section 8;
- (e) the manner of tapping the trees for resin under section 9;
- (f) the manner of registration under section 10, the period within which such registration shall be made, and the fees payable therefor;
- (g) specifications of resin for purposes of determination of quality;
- (h) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days, comprised in its one session or two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule shall not be made, the rule, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (3), any rules made within one year from the commencement of this Ordinance may be made retrospectively to a date not earlier than such commencement.

20. Where at any time before the commencement of this Ordinance, any person had entered into any contract for the sale of resin expected to be tapped by him to any trader and obtained an advance from such trader towards the price of the resin expected to be delivered to the trader under such contract, then notwithstanding that by virtue of the provisions of

Transitory provision.

sections 4 and 17, such contract shall have become void on the commencement of this Ordinance, the said person and trader may make a joint application before the Divisional Forest Officer or an officer authorised by him in that behalf giving particulars of such advance, and thereupon the said officer on being duly satisfied that the application has been voluntarily made by the said person may direct the officer to pay on behalf of the said person, to such trader a sum equivalent to the said advance (less the amount already repaid by the said person to such trader) without any interest or compensation, out of the price due to the said person for resin sold under section 8, and the liability of the State Government or the authorised officer to the said person and of the said person to the trader shall to the extent of such payment stand discharged, and the said person shall not be liable to pay any interest or compensation in respect of such advance.

AMINUDDIN AHMED KHAN,
*Governor,
Himachal Pradesh.*

SIMLA :
Dated the 13th February, 1981.

J. C. MALHOTRA,
Secretary (Law).